केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 203 शुक्रवार 13 फरवरी 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

अधूरी पड़ी ओवरहेड पानी की टंकियों का निर्माण पूरा कराने की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। सामाजिक कार्यकर्ता रामलोट ने जिलाधिकारी के माध्यम से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह को ज्ञापन देकर जनपद के हर्रैया तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज और दुबौलिया विकास खण्ड क्षेत्र में अधूरी पड़ी ओवरहेड पानी की टंकियों का कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने की मांग किया है।

ज्ञापन में रामलौट ने कहा है कि कप्तानगंज विकास खण्ड क्षेत्र के मरवटिया तिवारी, खेमराजपुर और दुबौलिया विकास खण्ड क्षेत्र के एकडेंगवा में मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा ओवरहेड पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था ने कार्य को अधूरा छोड़ दिया है और नागरिकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होने विभागीय मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह से मांग किया है कि अधूरे पड़े ओवरहेड पानी की टंकियों का निर्माण तत्काल प्रभाव से पूरा कराया जाय।

राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस

नई दिल्ली (आभा)। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफटाइम बैन लगाने की मांग की है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, सरकार राहुल के खिलाफ सदन में उनकी स्पीच के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदीजी ने छाती 56 इंच की नपवाई थी। उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए।

हालांकि, बीजेपी उनके (राहुल)

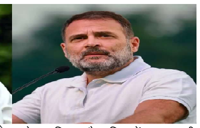

भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने आरोपों को लेकर सबूत पेश नहीं किए हैं। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है।

इससे पहले, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं।

हालांकि प्रियंका ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है। उन्होंने किसी को नहीं उकसाया। वे चुपचाप थीं। आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी थी।

अनियमितताओं पर भाजपा ने मण्डलायुक्त को सौंपा पत्र

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। भाजपा बस्ती जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए जा रहे अत्यधिक विकास शुल्क, प्राधिकरण में व्याप्त अनियमितताओं तथा बिजली विभाग और विजिलेंस विभाग की कार्यप्रणाली में सामने आ रही समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त अखिलेश सिंह को पत्र सौंपकर ठोस एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की।

पत्र में जिलाध्यक्ष ने कहा कि विनियमित क्षेत्र बस्ती के विघटन के पश्चात गठित बस्ती विकास प्राधिकरण में नगर पालिका क्षेत्र सहित 217 ग्रामों को शामिल किया गया है, जहाँ अधिकांश आबादी गरीब, मध्यमवर्गीय

एवं कृषक परिवारों की है। प्राधिकरण में शामिल होने के बाद भवन निर्माण, मरम्मत तथा जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण जैसे आवश्यक कार्यों पर भी विकास शुल्क लगाया जा रहा है, जिससे आमजन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

जिलाध्यक्ष के समर्थन में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा वर्मा, ब्लॉक प्रमुख बस्ती सदर श्री राकेश श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्री अभिषेक कुमार ने भी पत्र देकर अपनी सहमति दर्ज कराई। पत्र सौंपते समय बलराम सिंह, अंकुर वर्मा, अमृत कुमार वर्मा एवं गौरव अग्रवाल उपस्थित रहे।

आम आदमी पार्टी की 'नफरत मिटाओ, संविधान बचाओ' यात्रा 16 को

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। गुरूवार को आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष डा. राम सुभाष वर्मा की अध्यक्षता में प्रेस क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सांगठनिक मजबूती के साथ ही आगामी 16 फरवरी को सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज के बेवा चौराहे से कन्या इण्टर तक राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जाने वाली 'नफरत मिटाओ, संविधान बचाओ' 9 किलोमीटर की यात्रा की रूप रेखा पर विचार किया गया।

जिलाध्यक्ष डा. राम सुभाष वर्मा ने कहा कि 'नफरत मिटाओ, संविधान बचाओ' यात्रा में बस्ती से बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।

तैयारी बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी कुलदीप जायसवाल, प्रान्तीय सचिव पतिराम आजाद, जिला महासचिव चन्द्रभान कन्नौजिया आदि ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनहित के सवालों को लेकर निरन्तर संघर्षरत है। 'नफरत मिटाओ, संविधान बचाओ' यात्रा का उद्देश्य केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को आईना दिखाना है।

बैठक में मुख्य रूप से मिथिलेश भारती, शेषपाल चौधरी, राम सजन सूर्यबंशी, राम अदालत, वीरेन्द्र यादव आदि शामिल रहे।

मकान कब्जा कर लेने की नीयत से लगायी आग पीड़िता ने एसपी से लगाया न्याय की गुहार

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की महुडर रेहरवा निवासिनी अर्चना यादव पत्नी जितेन्द्र यादव ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर मकान पर कब्जा कर लेने की नीयत से आग लगा देने के मामले में दोषियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की मांग किया है।

एसपी को दिये पत्र में अर्चना यादव ने कहा है कि उनके

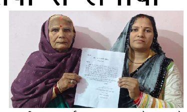

पटटीदार सूर्यभान यादव के लड़के हर्ष यादव के द्वारा उनके मकान को कब्जा करने की नीयत से 8 फरवरी को लगभग 3 बजे भोर में घर में आग लगा दिया गया जिसमें रखा हुआ शादी का सोफा, बड़ा बक्सा में भरा हुआ सामान और उसकी सास ससुर का समान जलकर राख हो गए हैं। इसमें काफी बहुमूल्य सामानों की क्षति हुई है। घटना की सूचना डायल 112 पर देने के साथ ही थाना पुरानी बस्ती में प्रार्थना पत्र दिया परन्तु अभी तक पुलिस के द्वारा अभियोग दर्ज नही किया गया। उसने मांग किया कि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के साथ ही उन्हें न्याय दिलाया जाय।

कलवारी–टाण्डा मार्ग पर नए आधुनिक पुल के निर्माण की मांगः सुभाष यदुवंश ने विधान परिषद में उठाया मुद्दा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने विधान परिषद में बस्ती जनपद को अम्बेडकर नगर से जोड़ने वाले कलवारी–टांडा मार्ग पर एक नए आधुनिक एवं चौड़े पुल के निर्माण की मांग उठाया।

सुभाष यदुवंश ने नियम 115 के तहत ध्यानाकर्षण करते हुये कहा कि यह पुल केवल दो जनपदों को जोड़ने का माध्यम नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती सहित अनेक जिलों को नेपाल सीमा से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सीमावर्ती आवागमन की दृष्टि से यह मार्ग रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस मार्ग पर केवल एक पुराना एवं अत्यंत संकरा पुल विद्यमान है, जिसकी चौड़ाई आज की यातायात आवश्यकताओं के

अनुरूप नहीं है। भारी वाहनों, यात्री बसों, एम्बुलेंस एवं दैनिक यातायात के कारण यहां निरंतर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे आम नागरिकों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ता है, दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।

विधानपरिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने कहा कि यह स्थिति केवल असुविधा का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक क्षति, समय की बर्बादी और जन–सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुकी है। पूर्वांचल के संतुलित विकास, नेपाल से व्यापारिक संपर्क को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस मार्ग पर एक नए, सुदृढ़ एवं आधुनिक पुल का निर्माण अब अत्यंत आवश्यक हो गया है।

सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में छात्रों को मिलेगा एक लाख रूपये का स्कालरशिप

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष जोशी ने बताया कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने हेतु लगातार 10 वर्षो तक जुड़े रहने पर 70 हजार और 12 वर्षो तक जुड़े रहने पर एक लाख रूपये का स्कालरशिप दिया जाता है।

प्रधानाचार्य सुभाष जोशी ने कहा कि देखिए, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है। अगर रीढ़ मजबूत

है तो पूरा देश मजबूती से खड़ा रहता है। आज भारत की शिक्षा प्रणाली में कई खूबियाँ हैं, लेकिन इसके साथ–साथ कुछ ऐसी कमियाँ भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए सुधार की जरूरत न केवल है, बल्कि यह समय की मांग बन चुकी है। कहा कि छात्र किताबें याद करके परीक्षा पास कर लेते हैं लेकिन असली ज्ञान और समझ विकसित नहीं हो पाती। हमें जरूरत है ऐसी शिक्षा प्रणाली की जो व्यावहारिक ज्ञान, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा दे। इस दिशा में सेठ एम.आर. जयपुरिया पूरी तरह समर्पण भाव से कार्य कर रहा है।

दारोगा अजय कुमार के रहस्यमयी मौत का मामला गरमाया गोंड महासभा ने सौंपा ज्ञापन, जांच, कार्यवाही की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। परशुरामपुर थाने में तैनात दारोगा अजय कुमार गोंड की संदिग्ध मृत्यु का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरूवार को अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा द्वारा जिलाध्यक्ष बलराम गौड़, उपाध्यक्ष गिरिजाशंकर गौड़ और महामंत्री अमित गौड़ के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चौक से प्रदर्शन करते हुये जुलूस निकाला गया। जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कड़ी कार्रवाई, परिजनों को सहायता दिलाये जाने की मांग किया गया।

डीएम को सम्बोधित ज्ञापन में कहा गया है कि दारोगा अजय कुमार गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से समूचा समाज आक्रोशित एवं व्यथित है। यह घटना न केवल एक अधिकारी की मृत्यु है, बल्कि

कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी खड़ा करती है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल प्रभाव ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सके। दिवंगत अधिकारी के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता एवं एक आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। घटना के दौरान हुई संभावित प्रशासनिक लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से अखिलेश गोंड, दयाराम गोंड, सचिन गोंड, परमेश्वर गोंड, आकाश गोंड, काशी प्रसाद गोंड, राजकुमार गोंड, आशुतोष गोंड, रूद्र गोंड, राजेश गोंड, राम सूरत गोंड, शुभम गोंड, राजू गोंड के साथ ही अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

ऐतिहासिक है केन्द्र और यूपी का बजट–संजय प्रताप जायसवाल

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरूवार को रूधौली विधानसभा क्षेत्र के अरदा मैरिज हाल के परिसर में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल के संयोजन में चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय बजट 2026 के प्रावधानों पर वक्ताओं ने जानकारी दी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कन्द्रीय और उत्तर प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक बताते हुये कहा कि इस बजट से गरीबों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। कहा कि विपक्ष के लोग बजट के बारे में जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं जबकि बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जिससे देश के नागरिकों को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी या नुकसान हो। कहा कि विपक्षी दलों के लोगों

–रूधौली के चौपाल में बजट की दिशा पर चर्चा

की टिप्पणियों से गुमराह न हों। उन्होने कहा कि बजट से लोगों के जीवन में बदलाव आयेगा। उन्होने ऐतिहासिक बजट के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया।

चौपाल में ब्लॉक प्रमुख गण, विधानसभा पदाधिकारी, मण्डल प्रभारी, मण्डल अध्यक्ष, मोर्चो व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, महिला शक्ति करण सहित सभी क्षेत्र के अनेक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता रही।

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, यशकान्त सिंह, पुष्करादित्य सिंह, दुष्यन्त विक्रम सिंह आदि ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों के लिए नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने वाला है।

कार्यक्रम में विजय तिवारी, रामनिवास गिरी राजेश उपाध्याय, अरविन्द चौरसिया, सुजीत सोनी, अतुल यादव, श्याम नाथ चौधरी, रामउग्र जायसवाल, प्रदीप सिंह, रवि प्रताप सिंह, के0 डी0 पाण्डेय राकेश, शमी विचिलमणि पाण्डेय, चन्द्रभान गुप्ता, प्रिंस जायसवाल, रजनीश चौधरी, मनोज सिंह, राजकुमार चौधरी, शैलेष, पप्पू चौधरी, जय प्रकाश जायसवाल, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, रिकू, विकी यमुना पाण्डेय, बबराम सिंह राहुल, कृपाशंकर श्रीवास्तव, शिव प्रसाद सोनी पप्पू यादव कोटेदार, क्षेत्रीय प्रधान, मोनू पाठक, अभिषेक त्रिपाठी, शिव प्रकाश सोनी, बंटू तिवारी मैलानी, बलराम तिवारी, संजय सिंह,, अशोक पाण्डेय, गोपाल सिंह, राकेश अग्रहरी, राम स्वरूप कसौधन, पंकज सिंह समासद, केशव पाठक, रणधीर सिंह, राधेश्याम पाठक, अवधेश मिश्रा, सोनू अग्रहरी, जुगनीलाल, फूलचंद्र शर्मा, फूले सोनकर, विपिन पाण्डेय, अनिल पाण्डेय के साथ ही भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

जयन्ती पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान पर विमर्शः जरूरतमंद छात्रों में किया स्वेटर का वितरण

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। शहर से सटे नगर पंचायत गनेशपुर स्थित एसपीपीवाई शिशु विद्यालय गनेशपुर बस्ती के परिसर में गुरूवार को आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। आयोजन सामाजिक संस्था सक्षम कल्चर सेवा समिति, के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, समाजसेवियों और छात्रों ने स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलने और 'वेदों की ओर लौटो' के संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। इसी कड़ी में जरूरतमंद 25 छात्र–छात्राओं में स्वेटर का वितरण किया गया।

मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉ. सत्येन्द्र प्रताप सिंह और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य अवनीश चौधरी ने मां सरस्वती और स्वामी दयानंद सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अवनीश चौधरी ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती केवल एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने भारत की सोई हुई चेतना को जगाया। आज के युवाओं को उनके 'सत्यार्थ प्रकाश' से प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षा

का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है, और यही स्वामी जी का मुख्य संदेश था। उन्होंने सक्षम कल्चर सेवा समिति के इस प्रयास की सराहना की कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक चेतना की अलख जगा रहे हैं।

डॉ. सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सक्षम कल्चर सेवा समिति, गणेशपुर बस्ती द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहा है।

सक्षम कल्चर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समिति बस्तियों और गाँवों में छिपी प्रतिभाओं को मंच देने और महापुरुषों के विचारों को जन–जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित है।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विद्यालय के छात्र–छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्रों ने देशभक्ति गीतों और स्वामी जी के जीवन पर आधारित कविताओं के माध्यम से समां बांध दिया। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत और सरस्वती वंदना ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार और समिति की ओर से सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनोज कुमार श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव, सुप्रिया श्रीवास्तव, विशाल, रमेश कुमार गुप्ता, शिक्षक संतोष कुमार यादव, शिक्षिका विमला देवी, समाजसेवी आलोक मिश्र, सूर्य प्रकाश वर्मा, दिनेश सिंह, अजय कसौधन, राघवेंद्र प्रताप, अनूप श्रीवास्तव, विवेक पांडेय, महेश शर्मा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ, सक्षम कल्चर सेवा समिति के सभी स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने निकाली मनरेगा बचाओ संग्राम पद यात्रा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। गुरूवार को कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डा. आलोक रंजन वर्मा के संयोजन में गोटवा से ' मनरेगा बचाओ संग्राम पद यात्रा' निकाली गई। यात्रा गोटवा से चलकर गनेशपुर होते हुये विभिन्न मार्गो से गांधी कला भवन पहुंची। बापू प्रतिमा के समक्ष यात्रा का समापन हुआ। सुदामागंज, गनेशपुर और शंकरपुर चौराहा पर नुक्कड सभाओं में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के नीति, कार्यक्रम पर निशाना साधा। कहा कि यह पूंजीपतियों की सरकार है जिसमें गरीब, किसान हाशिये पर हैं।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर नया कानून लाकर मोदी सरकार ने ''बुलडोजर चलाकर'' मनरेगा को खत्म किया। कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी और गरीबों, कृषि मजदूरों के हक हकूक को लेकर आन्दोलन जारी रहेगा। डा. आलोक रंजन वर्मा ने कहा कि

-गरीब किसानों, मजदूरों का हक छीन रही है भाजपा सरकार- विश्वनाथ चौधरी

-अन्याय का डटकर मुकाबला कर रही हैं कांग्रेस- डा. आलोक रंजन

हम मोदी सरकार द्वारा मनरेगा कानून को बदल देने के इस कदम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जो सरकार देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं का अपमान करे, वह सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती।'' लोग अब भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा समझ चुके हैं।

कांग्रेस नेता डा. वाहिद अली सिद्दीकी, शौकत अली नन्हू, अलीम अख्तर, राम पूरन चौधरी आदि ने कहा कि मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाकर मनरेगा अधिनियम को रद्द कर दिया। मनरेगा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था।'' कहा कि मनरेगा कानून संवैधानिक हक था, लोगों के पास रोजगार की कानूनी गारंटी थी और इस कानून से पंचायतें मजबूत हुईं। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के दबाव में गरीबों का हक छीन रही है। इसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।

मनरेगा बचाओ संग्राम पद यात्रा में मुख्य रूप से संदीप श्रीवास्तव, शब्बीर अहमद, साधु शरन आर्या,राकेश मणि त्रिपाठी, अनिल भारती, अमर बहादुर शुक्ला, आलोक त्रिपाठी, रविंद्र सिंह राजन, दूधनाथ पटेल,अवधेश सिंह,राहुल चौधरी, लाल जीत पहलवान, राजेश भारती, जमील कादरी, दिलीप श्रीवास्तव, चंद्रशेखर वर्मा, मोहम्मद अशरफ अली, आनंद निषाद, उमेश उपाध्याय, राज कपूर,अजय सिंह, बृजभान कनौजिया,शुभम गांधी, बसंत चौधरी, प्रिंस राणा, बलराम चौधरी,विजय चौधरी,विवेक पटेल, घनश्याम चौधरी, ध्रुव चौधरी, राकेश कुमार, जितेंद्र चौधरी, प्रमोद,रमेश चंद्र वर्मा, संजय चौधरी, दिनेश शर्मा,वीरेंद्र चौधरी, परशुराम,सुरेश, राम नयन यादव,रामबिहारे यादव,राम शंकर यादव, गजोधर यादव, अर्जुन चौधरी,डॉ सुरेंद्र सूरत चौधरी,बाबूराम वर्मा, लाल बहादुर चौधरी, रंजीत प्रमोद चौधरी, धर्मेंद्र वर्मा के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान, मजदूर शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक **भारतीय बस्ती**

बस्ती 13 फरवरी 2026 शुक्रवार

सम्पादकीय

एआइ, संभावना और आशंकायें

मशीनी कौशल यानी एआइ में इस पारंपरिक परिदृश्य को पलटने की क्षमता है। यदि बीसवीं सदी अभावों से पार पाने से जुड़ी थी तो आने वाला दशक अधिशेष के साथ संतुलन की चुनौती के नाम हो सकता है। नए परिदृश्य में तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से हमारी संस्थाएं पिछड़ती जा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उन नीतिगत उपायों पर विचार किया जाए जो एआइ से उत्पन्न उथल–पुथल से निपटने में कारगर साबित हो सकें।

पारंपरिक अर्थशास्त्र में उत्पादन के चार प्रमुख कारक–श्रम, पूंजी, भूमि और तकनीक माने गए हैं। तकनीक ने हमेशा श्रम को सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक तकनीकी संक्रमण उत्पादकता एवं पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ ही मांग के विस्तार और नई नौकरियों का माध्यम बना है। इससे कुछ असुविधा होती भी थी तो बस तात्कालिक ही न कि स्थायी, मगर एआइ से यह रुझान पलट सकता है। पहली बार तकनीक सीधे तौर पर श्रम को प्रतिस्थापित करती दिख रही है।

न केवल शारीरिक श्रम, बल्कि बौद्धिक, पेशेवर और रचनात्मक कामकाज के मामले में भी एआइ प्रभुत्व दिखा रही है। एआइ के साथ उत्पादकता तो बढ़ रही है, पर रोजगार सृजन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इससे साझा समृद्धि की राह प्रशस्त होने से रही। यानी विषमता बढ़ेगी। प्रकृति और स्वरूप में भी एआइ पिछली तकनीकों की तुलना में अलग है। इसका कोई प्रतिरूप एक बार आकार लेने पर यह सीमांत लागत को शून्य तक करने में सक्षम है। यह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार की स्थिति निर्मित करता है। कुछ देशों की चुनिंदा कंपनियों द्वारा विशेष प्रतिरूपों में महारत हासिल करने से यह झलकता भी है।

तमाम विश्लेषकों को आशंका सता रही है कि एआइ बड़े स्तर पर हलचल मचा सकती है। यह मानव समाज के संतुलन को भी प्रभावित करने में सक्षम है। आज उत्पादकता और क्षमताएं निरंतर बढ़ रही हैं। वस्तुएं सस्ती हो रही हैं। सेवाओं का स्तर सुधरा है। भौतिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। एआइ को सफलतापूर्वक अपनाने वाले देश तेज आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और बीमारियों पर बोझ घट रहा है। जीवन के विस्तार और काम का दायरा सिकुड़ने पर जननांकीय लाभांश अपने अर्थ खो देता है।

इस परिदृश्य में विदेश से भेजी जाने वाली धनराशि पर निर्भर राष्ट्र–समाज समस्याओं का सामना करते हैं। तब गरिमा और आजीविका के आधार के रूप में रोजगार का विचार संकट का शिकार होने लगता है। संसाधनों का संकेंद्रण भी एआइ के मोर्चे पर पैदा होने वाली एक और समस्या है। ऐसे में संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए कोई कारगर नीतिगत उपाय खोजना ही होगा। इसके अभाव में व्यापक आर्थिक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है।

एआइ के चलते सीखने–समझने की क्षमताओं पर भी संकट मंडराता दिख रहा है। जब मशीन ही फैसले लेने में भूमिका निभाने लगेगी तो लोगों में सीखने के प्रति झुकाव घटने का अंदेशा बढ़ता है। इतिहासकार डेविड रोकलिन ने यह रेखांकित भी किया था कि आटो–पायलट मोड पर अत्यधिक निर्भरता संकट के समय पायलटों के हाथ–पांव फुला देती है। बड़ा खतरा यह नहीं कि मशीन किसी इंसान की भांति काम करे, बल्कि यह खतरा कहीं विकराल होगा कि इंसान ही मशीन की तरह व्यवहार करने लगे।

एआइ की वजह से फर्जी सूचनाओं और तमाम संदिग्ध सामग्री का सैलाब भी संकट बढ़ा रहा है। इससे भरोसे की भावना पर आघात पहुंचा है। सत्य और मिथ्या को लेकर ऐसा जाल बुना जा रहा है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। एआइ पर पकड़ रखने वाले और ताकतवर बनने की राह पर हैं। इसके दम पर नव–धनकुबेरों का उभार हो रहा है।

भू–राजनीतिक संदर्भ में भी एआइ विषमता बढ़ा रही है, क्योंकि आधुनिक तकनीक से वंचित देश स्वतरू पिछड़ते जाएंगे। किसी देश की संप्रभुता पर किसी अन्य देश से संचालित हो रहे एलगोरिदम से ग्रहण लग सकता है। इस सबके बावजूद अगर सही नीतिगत उपाय किए जाएं तो एआइ बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी कर सकती है। इसके लिए एआइ को तकनीकी उपकरण से अधिक सभ्यतागत शक्ति के रूप में देखना होगा। एआइ का उपयोग मानव की जगह लेने के बजाय उसकी क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए।

एआइ उन तमाम समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, जिसके लिए असाधारण मानवीय प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बाहरी–अंतरिक्ष में कोई नया मोर्चा खोलना, गहरे समुद्र या पृथ्वी की जटिल परतों के रहस्यों को सुलझाना। इससे कई ग्रहों पर मानवीय जीवन को संभव बनाया जा सकता है। हम प्रकृति को बेहतर तरीके से समझकर उसके कुशल प्रबंधन के मंत्र समझ सकते हैं। तथ्यों एवं सूचनाओं के सत्यापन के लिए भी इसकी सेवा कारगर होगी। यह स्वीकारने में कोई संदेह नहीं कि एआइ कितनी भी क्षमताएं अर्जित कर ले, लेकिन उसका प्यार, देखभाल, समानुभूति और नैतिक दायित्वों जैसी मानवीय भावनाओं से युक्त होना संभव नहीं है। एआइ से मरीज का उपचार भले ही बेहतर हो जाए, लेकिन प्यार–दुलार और देखभाल प्रियजनों से ही संभव है। हमें समझना होगा कि एआइ कोई प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं, बल्कि एक साझा दायित्व है। वसुधैव कुटुंबकम् का भारतीय विचार अब दर्शन के दायरे से निकलकर अस्तित्व की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में, भारत अपनी सभ्यतागत गहराई और विश्वसनीयता के माध्यम से नए शासकीय ढांचों के लिए वैश्विक एआइ मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कृषि उपज के लिए बाजार को खोलने के खतरे

–उमेश चतुर्वेदी–

भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी।

इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बरसों से भारतीय कृषि बाजार में बड़ी और व्यापक पहुंच हासिल करने की कोशिश में है। हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान 18 प्रतिशत के ही टैरिफ पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर मनमाने तरीके से थोपे गए पचास प्रतिशत के टैरिफ के मुकाबले मौजूदा व्यापार समझौते के तहत अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 18 प्रतिशत का टैरिफ कम ही कहा जाएगा। हालांकि अतीत के करीब तीन प्रतिशत के मुकाबले फिर भी यह बहुत ज्यादा है। बहरहाल इसी समझौते के मद्देनजर जिस तरह से अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक लेस्ली रोलिंग्स ने खुशी जताई, उससे भारतीय किसान आशंकित हो उठे।

भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। रोलिंग्स यहीं पर नहीं रूके। उन्होंने सिर्फ 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत के साथ कृषि कारोबार के चलते अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। रोलिंग्स ने उम्मीद जताई कि नए व्यापार समझौते की वजह से विशाल आबादी वाला भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है।

रोलिंग्स की इस खुशी की वजह से भारतीय किसानों का आशंकित होना जायज है। अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा पचास अरब डॉलर है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले। भारत की चिंता की वजह उसकी खेती–किसानी वाली बड़ी जनसंख्या है। भारत के छियासी प्रतिशत किसान सीमांत या लघु हैं। जिनकी जोत दो हेक्टेयर से कम है। भारत में खेती पर करीब 10.7 करोड़ परिवार निर्भर हैं। यह जनसंख्या का करीब बासठ प्रतिशत है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसने की अनुमति मिलती है तो भारी सब्सिडी के चलते भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। इससे भारतीय किसानों के सामने संकट उठ खड़ा हो सकता है।

किसानों की आशंकाओं को विपक्षी दलों ने अपने ऊंचे सुरों से और बढ़ाया ही है। लेकिन कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि भारत–अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। चौहान का यह भी कहना है कि इस कारोबारी समझौते से देश के मुख्य खाद्यान्नों, मिलेट्स, फलों,सब्जियों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह अलग रखा गया है। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, इस समझौते से भारतीय किसानों को नए अवसर मिलेंगे,क्योंकि इस समझौते में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से अमेरिका समेत कई देशों को करीब 63 हजार करोड़ के चावल का निर्यात कर चुका है। भारत सरकार का दावा है कि नए टैरिफ समझौते से भारतीय किसानों के चावल और मसालों के साथ ही टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा।

भारत–अमेरिकी समझौते के तहत भारत को अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर का सामान पांच सालों में खरीदना है। वैसे समझौते पर जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसके तहत भारतीय कृषि बाजार को भी खोलने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस समझौते से, भारतीय चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाजों को बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बाहर हैं। ऐसा करने की वजह यह है कि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग को कारोबारी परेशानियां न झेलनीं पड़ें। वैसे भी भारत लंबे समय से कृषि और डेयरी उद्योग को 'रेड–लाइन' यानी किनारे रखने वाला सेक्टर मानता रहा है। इसकी वजह है कि गांवों में इनसे जुड़े काफी रोजगार हैं। इन सेक्टर को खोलने को लेकर भारत की बातचीत यूरोप और ब्रिटेन से भी अटक चुकी है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस बाजार को खोलना भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक तो होगा ही, राजनीतिक बवंडर की वजह भी बन सकता है। इस बवंडर का सामना करने की हिम्मत विरली राजनीतिक ताकतें ही कर सकती हैं। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासतौर पर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए तीन लाख अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा बाजार खुलने की उम्मीद है। इसकी वजह से जो निर्यात बढ़ेगा, उससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, एथनॉल, तंबाकू, सब्जियां और मांस सहित संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों को पूर्ण रूप से संरक्षित करेगा। दोनों देश अपने–अपने हित वाले क्षेत्रों में एक–दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में भारत ने अमेरिका से 2.4 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद आयात किए थे, जिनमें ज्यादातर ताजे फल, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट मादक पेय, कच्चा कपास, वनस्पति तेल और प्रोसेस्ड सामान हैं। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को 6.2 अरब डॉलर का कृषि निर्यात किया, जिनमें समुद्री उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, जड़ी–बूटियों के आयुर्वेदिक उत्पाद प्रमुख रहे। यह भारत के कुल 53.2 अरब डॉलर सालाना के कृषि निर्यात का 11.74 प्रतिशत है। कृषि और डेयरी उत्पाद के कारोबार के इसी असुंलन की वजह से अमेरिका भारतीय बाजार में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सूत्र इससे साफ इनकार कर रहे हैं। भारत के सामने संकट यह है कि अगर उसने इस क्षेत्र को खोला तो छोटे और सीमांत किसानों के सामने जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनसे वह कैसे निबट पाएगा।

गड्ढों वाली व्यवस्था के खतरे और तंत्र

–ललित गर्ग –

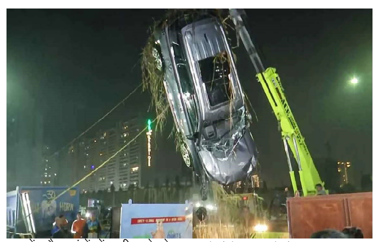

गड्ढों में गिरी व्यवस्था में समाप्त होता जीवन आज के भारत की एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर मन भीतर तक सिहर उठता है। नोएडा में कार सवार युवा इंजीनियर की गड्ढे में गिरकर मौत का दर्द अभी समाज के मन से उतरा भी नहीं था कि दिल्ली में बाइक सवार युवक की जान एक खुले गड्ढे ने लील ली। दोनों घटनाओं में समानता यह है कि गड्ढे प्रशासन द्वारा विकास या मरम्मत के नाम पर खोदे गए थे और दोनों जगह न तो कोई बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न रोशनी की व्यवस्था। मानो व्यवस्था ने पहले गड्ढा खोदा और फिर निश्चिंत होकर वहां से हट गई कि अब जो होगा, वह नागरिक की किस्मत है। यही वह सोच है जो किसी भी समाज को भीतर से खोखला कर देती है।

प्रश्न यह नहीं है कि गड्ढे क्यों खोदे गए, प्रश्न यह है कि गड्ढे खोदकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया। क्या विकास का अर्थ यह हो गया है कि सड़कों पर चलते हुए हर नागरिक अपनी जान हथेली पर रखे। क्या शहरों की चमक–दमक और बड़े–बड़े दावों के बीच आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। यह सामान्य हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब मौतें सामान्य लगने लगें, तब व्यवस्था की संवेदनशीलता मर चुकी होती है।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा हो या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निलंबित कर दिए जाते हैं, जांच समितियां बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है। सवाल यह है कि क्या निलंबन से मरे हुए बेटे लौट आते हैं, क्या जांच समितियों से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जब तक जवाबदेही केवल कागजों पर सिमटी रहेगी, तब तक गड्ढों में गिरती जिंदगियां यूं ही व्यवस्था का शिकार बनती रहेंगी।

इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कम से कम चर्चा में तो आती हैं, मीडिया सवाल तो उठाता है, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में यही गड्ढे रोज जिंदगियां निगल रहे हैं और खबर तक नहीं बनते। वहां न कैमरा पहुंचता है, न कोई प्रतिनिधि, न कोई जांच समिति। वहां मौतें सिर्फ परिवारों की निजी त्रासदी बनकर रह जाती हैं। क्या नागरिक का मूल्य शहर के आकार से तय होगा। क्या महानगरों का नागरिक ज्यादा कीमती है और छोटे शहरों का नागरिक सस्ता। यह असमानता केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि संवेदनाओं की भी है।

हम एक ओर विकसित भारत, सशक्त भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी सड़कों पर खुले गड्ढे हमें आईना दिखाते हैं। विकास की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन यदि उस रफ्तार में सुरक्षा, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना नहीं जुड़ी, तो वह रफ्तार विनाश की ओर ही ले जाएगी। यह विडंबना ही है कि हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, लेकिन स्मार्ट बैरिकेडिंग, स्मार्ट चेतावनी और स्मार्ट जिम्मेदारी पर बात करना भूल जाते हैं। तकनीक के युग में भी एक साधारण चेतावनी बोर्ड लगाना हमारे तंत्र को याद नहीं रहता।

दरअसल समस्या केवल लापरवाही की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें नागरिक को एक आंकड़ा समझ लिया गया है। फाइलों में वह एक केस नंबर है, सड़क पर वह एक बाधा और हादसे के बाद वह एक आंकड़ा। जब तक प्रशासन और शासन की दृष्टि में नागरिक का जीवन सर्वोपरि मूल्य नहीं बनेगा, तब तक हर नया गड्ढा एक नई मौत की संभावना बनकर खड़ा रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या इन गड्ढों के लिए कभी उच्च स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी तय होगी। क्या कभी ऐसा होगा कि किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके विभाग की लापरवाही से एक जान गई, इसलिए आप पद पर बने रहने के नैतिक अधिकारी नहीं हैं।

भ्रष्ट शासन के समाप्त होने की बड़ी–बड़ी घोषणाएं हर चुनाव में सुनाई देती हैं। पोस्टर बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जमीन पर गड्ढे वैसे ही रहते हैं। यदि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित होता तो शायद उसे पहचानना आसान होता, लेकिन यह जो संवेदनहीन भ्रष्टाचार है, जहां नियमों की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की उपेक्षा और समय पर काम पूरा न करना शामिल है, यह ज्यादा खतरनाक है। इसमें पैसा दिखता नहीं, लेकिन इसकी कीमत किसी की जान से चुकानी पड़ती है।

आज जब हम अमृत काल और शताब्दी वर्ष में नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, तब यह प्रश्न और भी तीखा हो जाता है कि क्या खुले गड्ढों वाला देश महान बन सकता है। क्या वह देश विकसित कहलाने योग्य है, जहां नागरिक रात को सड़क पर निकलते समय यह दुआ करे कि कहीं कोई गड्ढा उसकी जिंदगी न छीन ले। विकास केवल पुलों, सड़कों और इमारतों से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है। यदि सुरक्षा का भरोसा नहीं, तो सारी उपलब्धियां खोखली हैं।

गड्ढों में गिरी व्यवस्था केवल सड़कों की समस्या नहीं है, यह हमारे शासन तंत्र की नैतिक गिरावट का प्रतीक है। यह उस दूरी को दिखाता है जो सत्ता और नागरिक के बीच बढ़ती जा रही है। जब तक हर गड्ढे को सिर्फ तकनीकी खामी समझा जाएगा और हर मौत को दुर्भाग्य कहकर टाल दिया जाएगा, तब तक यह सिलसिला रुकेगा नहीं। जरूरत इस बात की है कि हर गड्ढा एक सवाल बने, हर मौत एक चेतावनी और हर लापरवाही एक अपराध मानी जाए।

कब वे गड्ढे भरेंगे, कब व्यवस्था की दरारें बंद होंगी और कब विकास की दौड़ में भागता देश यह भरोसा पाएगा कि वह सुरक्षित हाथों में है, यह सवाल आज हर नागरिक के मन में है। शायद उस दिन हम सचमुच कह सकेंगे कि हमारा देश महान बनने की राह पर है। अभी तो लगता है कि हम महान नहीं, बल्कि परेशान हैं और यह परेशानी सिर्फ गड्ढों की नहीं, गड्ढों में गिरती संवेदनाओं की है।

शिक्षा का वैश्वीकरण या नई असमानता की शुरुआत

–राजेश जैन–

हाल ही में खबर आई थी कि नौ ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में यह टर्निंग पॉइंट 2023–24 से आया था। तभी से दुनिया के नामी विश्वविद्यालयों ने हमारे देश की जमीन पर अपने स्वतंत्र कैंपस खोलना शुरू किया। यह बदलाव यूँ ही नहीं आया। इसके पीछे है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस रेगुलेशंस– 2023 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी– 2020 की वह सोच, जिसमें भारत को "वैश्विक शिक्षा केंद्र" बनाने का सपना देखा गया है। आज यह सपना धीरे–धीरे हकीकत में बदल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात में पढ़ाई शुरू करवा दी है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्प्टन, गुरुग्राम में अपना कैंपस खोल चुकी है। हैं इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी और क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है। सवाल यह नहीं है कि विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं। असली सवाल है–इससे भारत को क्या मिलेगा, क्या खो सकता है और इसे कैसे संतुलित किया जाए?

भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा बाजार है। 30 वर्ष से कम उम्र की आबादी 50ः से ज्यादा है, लेकिन उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात अभी भी लगभग 30ः के आसपास है। यानी करोड़ों युवा ऐसे हैं, जो बेहतर शिक्षा के मौके तलाश रहे हैं। दूसरी ओर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के विश्वविद्यालय घरेलू नामांकन में ठहराव और सरकारी फंडिंग में कटौती झेल रहे हैं। हालिया वीजा सख्ती ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी प्रभावित की है। ऐसे में भारत उनके लिए हाई–पोटेंशियल मार्केट बनकर उभरा है। यहां अंग्रेजी बोलने वाले छात्र हैं, उभरता मध्यम वर्ग है और अंतरराष्ट्रीय डिग्री की मजबूत मांग है। आसान शब्दों में कहें तो यह विन–विन मॉडल है–विदेशी संस्थानों को नया बाजार, भारत को ग्लोबल एजुकेशन का एक्सेस।

सबसे बड़ा फायदा है–घर बैठे विदेशी डिग्री। अब भारतीय छात्रों को मास्टर्स या स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए विदेश जाने, लाखों की फीस, वीजा तनाव और महंगे जीवन–यापन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुमान है कि भारत में वही डिग्री 25द30ः कम लागत में मिल सकेगी। इसके साथ उनको अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम, इंडस्ट्री–फोकस्ड ट्रेनिंग, ग्लोबल फैकल्टी एक्सपोजर, बेहतर रिसर्च कल्चर भी मिलेंगे। बिजनेस एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, कंप्यूटिंग जैसे कोर्स सीधे भविष्य की नौकरियों से जुड़े हैं। इससे स्किल गैप कम हो सकता है और भारतीय ग्रेजुएट्स की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है।

2019 में करीब 5.8 लाख भारतीय छात्र विदेश गए थे। 2023 में यह संख्या 9 लाख तक पहुंच गई। इनमें से 75ः से ज्यादा वहीं बसने की इच्छा रखते हैं। इसका मतलब–देश से प्रतिभा भी जा रही है और अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा भी। अगर यही गुणवत्ता भारत में उपलब्ध हो जाए, तो "ब्रेन ड्रेन" की जगह "ब्रेन रिटेंशन" संभव है। विदेशी कैंपस देश के भीतर ही अंतरराष्ट्रीय माहौल तैयार कर सकते हैं।

विदेशी विश्वविद्यालय सिर्फ क्लासरूम नहीं लाते–वे साथ लाते हैं रिसर्च कल्चर, गवर्नेंस मॉडल और अकादमिक डिसिप्लिन। संयुक्त रिसर्च सेंटर, फैकल्टी एक्सचेंज और साझा प्रोजेक्ट्स के जरिये भारतीय संस्थानों की क्षमता बढ़ सकती है। पहले से ही भारत के पास मजबूत आधार है–जैसे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसे संस्थान। सही सहयोग हुआ तो भारत सिर्फ स्टूडेंट–सोर्स देश नहीं रहेगा, बल्कि नॉलेज–प्रोड्यूसर बनेगा।

सबसे बड़ी चिंता है–वहनीयता। विदेशी कैंपस की फीस भले विदेश से कम हो, लेकिन भारतीय औसत आय के हिसाब से यह अभी भी बहुत ज्यादा है। खतरा यह है कि ये संस्थान सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित रह जाएं। इससे शिक्षा में सामाजिक असमानता और गहरी हो सकती है–जो नई शिक्षा नीति– 2020 के समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के खिलाफ है।दूसरी चुनौती है–व्यावसायीकरण। अगर रेगुलेशन कमजोर रहा, तो कुछ विदेशी संस्थान शिक्षा को प्रोडक्ट की तरह बेच सकते हैं। चीन और दक्षिण–पूर्व एशिया के उदाहरण बताते हैं कि कम नामांकन और ऊंची लागत के कारण कई विदेशी कैंपस कुछ साल में बंद भी हो गए। तीसरा मुद्दा है–स्थानीय प्रासंगिकता। अगर पाठ्यक्रम भारतीय सामाजिक–आर्थिक जरूरतों से कटे रहे, स्थानीय फैकल्टी शामिल न हो और इंडियन कॉन्टेक्स्ट गायब हो तो ये कैंपस "एलिट आइलैंड" बनकर रह जाएंगे।

यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम, फीस और प्रवेश में काफी स्वायत्तता दी है ताकि वे तेजी से काम शुरू कर सकें। लेकिन अब जरूरत है स्मार्ट रेगुलेशन की। हमें ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें टॉप–रैंक संस्थानों को ऑपरेशनल फ्रीडम मिले, फीस स्ट्रक्चर पारदर्शी हो, छात्र अधिकार सुरक्षित रहें, न्यूनतम छात्रवृत्ति को अनिवार्य किया जाए और अकादमिक गुणवत्ता की नियमित ऑडिट हो।

हर विदेशी कैंपस में इडब्यूएस और वंचित वर्ग के लिए स्कॉलरशिप अनिवार्य की जाए, अकेले कैंपस नहीं–भारतीय संस्थानों के साथ साझा मॉडल को बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च और फैकल्टी डेवलपमेंट को प्राथमिकता मिले, सिर्फ टीचिंग तक सीमित न रहा जाए, पाठ्यक्रमों का भारतीयकरण हो ताकि वे यहां की अर्थव्यवस्था, समाज और उद्योग से जुड़े रहें और दीर्घकाल में भारत को अपनी "आईवी लीग" तैयार करनी होगीकृजहां आईआईटी , आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर हों।

विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत आना सिर्फ शिक्षा सुधार नहीं–यह कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर से भी जुड़ा है। सही नीति के साथ यह पहल भारत को एशिया का एजुकेशन हब बना सकती है लेकिन अगर इसे केवल बाजार के हवाले छोड़ दिया गया तो यह अमीरों की शिक्षा बनकर रह जाएगी। आज भारत एक दोराहे पर खड़ा है– एक रास्ता वैश्विक ज्ञान नेतृत्व की ओर जाता है, दूसरा नई शैक्षिक असमानता की तरफ। फैसला हमें करना है।

मुठभेड़ में तीन शातिर चोर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

संवाददाता—गोण्डा। बाइक सवार तीन शातिर चोरों के साथ बुधवार की देर रात एसओजी व इकौना की संयुक्त पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। चोरों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से एक चोर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने सीएचसी में भर्ती करवाया है। मुठभेड़ के दौरान भाग रहे घायल चोर के दो साथियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार चोरों के पास से आभूषण व हथियार बरामद हुआ है। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने बताया कि बुधवार की रात इकौना थाना प्रभारी परमानंद तिवारी पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान मोहनीपुर चौराहे से कैलाशपुर मार्ग हाइवे मोड़ के पास शातिर चोरों के मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी ने एसओजी टीम के साथ कैलाशपुर हाईवे मोड़ पर चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार तीन संदिग्ध मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने जैसे ही तीनों को रोकने का इशारा किया तो एक संदिग्ध ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार शातिर चोर सीतापुर जिले के थानगांव थाना क्षेत्र के ग्वारी गांव निवासी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पासी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, उसके साथ मौजूद दो अन्य शातिर चोरों को भी भागते समय दबोच लिया गया। उनकी पहचान ग्वारी गांव निवासी राजू सिंह और रामचन्दर के रूप में हुई है। तीनों को जेल भेज दिया गया।

ईंट—पत्थर फेंक कर पता करते थे मौजूद लोगों की संख्या

एएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया कि वो सभी दिन के समय विभिन्न गांवों में घूमकर गांव के बाहर स्थित घरों की रेकी करते थे। चोरी के लिए उस घर का चुनाव करते थे, जहां पहुंचने का रास्ता आसान हो और आसपास छिपने की जगह हो। यही नहीं चोरी से पहले ये चिन्हित घर पर पत्थर व ईंट फेंक कर घर में मौजूद सदस्यों की संख्या की जांच करते थे। संतुष्टि के बाद घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। एएसपी ने बताया कि इस गिरोह ने इकौना क्षेत्र में दो से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था।

लंबा है आपराधिक इतिहास, आभूषण व हथियार बरामद

एएसपी ने बताया कि पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। रामप्रकाश पर सीतापुर व श्रावस्ती में विभिन्न थानों में 23 प्राथमिकी, राजू सिंह पर श्रावस्ती व सीतापुर में विभिन्न थानों में सात प्राथमिकी और रामचंद्र पर श्रावस्ती जिले में छह प्राथमिकी दर्ज है। चोरों के पास से सोने—चांदी के आभूषण, 25,000 रुपये नकद, चोरी में प्रयुक्त औजार पेंचकस, सब्बल, आरी ब्लेड, कटर, घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की बाइक व हथियार बरामद हुआ है।

चुपके से निकल गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, नहीं लगी किसी को भनक

संवाददाता—देवरिया। धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर दो माह बाद बुधवार की रात देवरिया जेल से रिहा हो गए। वह अकेले ही जेल से बाहर आए और कार में बैठकर कहीं चले गए। अमिताभ ठाकुर कहां गए, किसी को नहीं पता चला है। चलती ट्रेन से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। पहले वाराणसी के मामले में जमानत मिली फिर 19 जनवरी को देवरिया के धोखाधड़ी मामले में जमानत मंजूर हो गई थी। जमानतदारों के सत्यापन होने के बाद न्यायालय से जेल पहुंचे रिहाई परवाना के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की भनक न तो देवरिया पुलिस को लगी और न ही 10 दिनों से डेरा डाले लखनऊ पुलिस को लग सकी।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धोखाधड़ी के मामले में 10 दिसंबर को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन से वह देवरिया जेल में बंद थे। 19 जनवरी को देवरिया जेल से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन बेल बांड उस समय उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया गया। जब वाराणसी में दर्ज मुकदमे में उन्हें जमानत मिली और उनका जमानत परवाना जेल पहुंच गया तो देवरिया जिला जज की अदालत में अधिवक्ता ने बेल बांड जमा किया और उनका सत्यापन पूरा हो गया। देर शाम जेल रिहाई कागजात पहुंचा। जिसके बाद उन्हें रात की रिहाई में रिहा कर दिया गया। जेलर राजकुमार ने बताया कि न्यायालय का अनुपालन करते हुए उन्हें रात को रिहा कर दिया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध लखनऊ में एक धोखाधड़ी का केस दर्ज है। जब देवरिया जिला जज की अदालत से उनकी जमानत हो गई तो लखनऊ में दर्ज केस में वारंट बी देवरिया न्यायालय से पहुंच गया। 30 जनवरी को लखनऊ की अदालत ने जमानत बी वारंट खारिज कर दिया।

विदाई समारोह में छात्रों को बताए सफलता के मंत्र

—संवाददाता भारतीय बस्ती— बस्ती (बनकटी)। सूर्य बक्श पाल बालिका इंटर कॉलेज बनकटी परिसर में कक्षा 12 की छात्राओं के लिए विदाई (आशीर्वाद) समारोह का भव्य आयोजन उमेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। विद्यालय परिवार ने छात्राओं को भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

समारोह में मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा मेधावी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्र—छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. अजीत प्रताप सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन, निरंतर परिश्रम और सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी से प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलती है। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक उमेश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय से मिली शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास बनाए रखने, समय का सदुपयोग करने और अपने माता—पिता व गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम पांडेय ने प्रभावी ढंग से किया।

इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को भावुक और यादगार बना दिया। विद्यालय परिवार की ओर से छात्राओं को स्मृति—चिह्न भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

इस अवसर पर मंदाकिनी पाल, अल्तिमा, प्रीति, जया शुक्ला, प्रभाकर, एस.पी. चौधरी, धन्नजय सिंह, रवि श्रीवास्तव, राधेश्याम पांडेय सहित अनेक अभिभावक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सभी ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

महाशिवरात्रि पर ड्रोन से निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

संवाददाता—श्रावस्ती। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने थाना सिरसिया क्षेत्र के पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर सिरसिया और श्री काली माता मंदिर, भिनगा का संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती, ड्यूटी प्वाइंट, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, प्रवेश—निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग, पेयजल और साफ—सफाई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के प्रबंधों का भी जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पर्व के दिन कोई अव्यवस्था न हो और सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुदृढ़ कर ली जाएं।

जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने बताया कि महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा और सुविधा दोनों पर समान ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और मंदिर प्रबंधन समिति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जानकारी दी कि पर्व के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी और प्रमुख स्थलों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए एक विशेष ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, प्रशासन के दिशा—निर्देशों का अनुपालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि समुचित सुरक्षा प्रबंधों और समन्वित प्रयासों से महाशिवरात्रि पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धा—भक्ति के वातावरण में संपन्न होगा।

तीन शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 10 बाइक बरामद

संवाददाता—बहराइच। जिले की भारत—नेपाल सीमा पर पुलिस ने तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की दस मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये चोर भारतीय क्षेत्र से वाहन चुराकर उन्हें नेपाल में बेच देते थे।

रूपईडीहा थाना प्रभारी रमेश रावत ने बताया कि उप निरीक्षक दीनानाथ भास्कर, राहुल सरोज, आरक्षी अभिषेक राय और रविंद्र यादव पचपकड़ी तिराहा से कुछ दूरी पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रोककर वाहन के कागजात मांगे, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि बाइक चोरी की है। हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने सीमा से लगे चकिया जंगल में चोरी के अन्य वाहन छिपाकर रखने की बात कबूली। पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी कर मौके से चोरी की नौ अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद कीं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान शाहरुख खान, अरमान खान और नफीस खान के रूप में हुई है। ये सभी नेपाल के बांके जिले के निवासी हैं। ये चोर लखनऊ, लखीमपुर और बहराइच सहित जिले के अन्य इलाकों से वाहन चुराते थे और फिर उन्हें सीमा पार नेपाल में बेच देते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है।

सड़क पार कर रहे शख्स को कार ने रौंदा, मौत

संवाददाता—महराजगंज। फरेंदा क्षेत्र के रुनुवा चौराहे पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क पार कर रहे एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। कार की ठोकर से यह शख्स काफी ऊंचाई तक उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसको बचने की आस में लोगों ने आनन—फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फरेंदा क्षेत्र के रामनगर टोला जानकी नगर निवासी रामनयन (50) किसी काम से सड़क पार कर रहा था।

इसी दौरान तेज गति से कार आती दिखी। रामनयन कार की रफ्तार देख हड़बड़ा गया और जब तक वह कुछ समझ पाता कि कार ने सीधे उसको ठोकर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रामनयन उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा—तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरेन्दा भिजवाया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। सीएचसी में पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच के बाद रामनयन को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। एक सीसीटीवी की फुटेज में वाहन की तस्वीर स्पष्ट होने की बात कही जा रही है और पूरी घटना कैद हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस फुटेज से पुलिस को क्लू मिल गया है। घर में कोहराम, पसरा मातम घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरार चालक को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिवक्ताओं में उबाल, जिले भर में प्रदर्शन

संवाददाता—महराजगंज। रामपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता फारूख अहमद खान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के विरोध में गुरुवार को जिले में अधिवक्ताओं में उबाल रहा। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महराजगंज सहित सभी तहसीलों में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महराजगंज के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में न्यायालय परिसर से कलक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। हत्यारों की 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी, एक करोड़ रुपये मुआवजा व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी सौंपा। अध्यक्ष ने कहा कि 11 फरवरी को हुई इस जघन्य वारदात ने पूरे प्रदेश के वकील समुदाय को झकझोर दिया है। कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का मजबूत स्तंभ हैं, और उनकी सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो प्रदेश स्तर पर धरना—प्रदर्शन, आमरण अनशन व व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सुशील श्रीवास्तव, अरविन्द प्रताप निषाद, घनश्याम तिवारी, अरुण कुमार सिंह, रंजीत कुमार गुप्ता, अर्जुन, पवन कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, हीरा लाल चौरसिया आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में फरेंदा, निचलौल व नौतनवा तहसीलों में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

डीएम ने विकास कार्यों का किया निरीक्षणः मनरेगा कर्मियों पर कार्रवाई, अभिलेख अपडेट न होने पर दिए सख्त निर्देश

संवाददाता—बलरामपुर। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने विकास खंड बलरामपुर सदर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां पाईं। अभिलेखों में अनियमितता, योजनाओं की धीमी प्रगति और निर्माण कार्यों में सुस्ती पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभिन्न पटलों के रजिस्टरों और अभिलेखों की गहन जांच की।

जिलाधिकारी ने सभी रजिस्टरों को नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षों से लंबित पड़ी पुरानी और निष्प्रयोज्य पत्रावलियों को समयबद्ध तरीके से हटाने (वीड आउट) और कार्यालय व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया।

पेंशन योजनाओं के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवेदनों पर रिपोर्ट लगाकर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

विकास खंड परिसर में संचालित आधार केंद्र का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान मनरेगा सेल में अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही और कार्यों में सुस्ती पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा कदम उठाते हुए मनरेगा के लेखा सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की संविदा समाप्त करने तथा नए कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। कन्वर्जेंस से बनाए जा रहे नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर भी डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और कार्यों में तेजी लाने का अल्टीमेटम दिया।

उन्होंने सभी ग्राम सचिवों को निर्देशित किया कि नए आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूरा किया जाए।

सहायक विकास अधिकारी पटल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर परिवार रजिस्टर अद्यतन करने और प्रत्येक परिवार को उसकी नकल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने 'जीरो पेंडेंसी' सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

कोटेश्वरी देवी मंदिर के गर्भ गृह में महिला ने की तोड़फोड़ गिरफ्तार

संवाददाता—कुशीनगर। मैनपुर कोटेश्वरी देवी मंदिर के गर्भ गृह में घुसी एक महिला ने पिंडी तोड़ दी। चरण पादुका खंडित कर दिया। बगल में रखी हनुमान जी की मूर्ति को बाहर फेंक दिया। पिंडी पर चढ़ाए गए चुनरी एवं फूल आदि सामग्री को फेंक कर वहीं बैठ गई। गुरुवार की सुबह पूजा के लिए श्रद्धालु पहुंचे तो उसे पकड़ कर बाहर किया और पुलिस को सौंपा। जांच पड़ताल के बाद महिला को अर्धविक्षिप्त बताते हुए कसया थाना पुलिस ने स्वजन के सिपुर्द कर दिया। सुबह रोज की भांति श्रद्धालु मंदिर में पूजन अर्चन के लिए पहुंचे तो परिसर की हालत देख कर दंग रह गए। गर्भ गृह में स्थापित देवी की चरण पादुका बाहर खंडित पड़ी थी। हनुमान जी की मूर्ति भी अपने स्थान से हटी मिली, देखा तो बाहर फेंका गया है। गर्भ गृह में पिंडी पर चढ़ाई गई चुनरी और फूल आदि सामग्री बिखरा पड़ी थी। एक महिला वहीं बैठी थी। श्रद्धालुओं ने पकड़ कर उसे बाहर निकाल कर बैठा दिया। पुलिस आई तो महिला उन पर ईंट, पत्थर चलाने लगी। लोगों ने उसे काबू में किया। बताया जा रहा है कि मंदिर में लगे सीसी कैमरे काफी दिनों से खराब पड़े हैं। इस प्रसिद्ध देवी मंदिर में प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस ने छानबीन की तो आरोपित महिला मैनपुर टोला खदही के अच्छेलाल की पत्नी 35 वर्षीय कांति देवी निकली। स्वजन से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वह अर्द्ध विक्षिप्त है , गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। थानाध्यक्ष अभिनव मिश्र ने मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से इन्कार करते हुए बताया कि, अर्द्ध विक्षिप्त महिला ने केवली सामग्री तितर—बितर की थी।

अमेरिका—भारत कृषि डील के विरोध में गरजे भाकियू कार्यकर्ता

संवाददाता—महराजगंज। अमेरिका—भारत कृषि व्यापार समझौते के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर धरना—प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राम अशीष की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी आंदोलन के तहत कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। खेती, बीज व दुग्ध उत्पादन पर खतरा बताते हुए समझौता तत्काल रद्द करने की मांग की। जिलाध्यक्ष रामअशीष ने कहा प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौता देश की लगभग 70 प्रतिशत कृषि आधारित आबादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उनका आरोप है कि पहले से बाजार की अनिश्चितता, बढ़ती लागत व कर्ज के बोझ से जूझ रहे किसानों की स्थिति इस समझौते के लागू होने पर और गंभीर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शून्य प्रतिशत आयात शुल्क लागू करता है, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैरिफ वसूलता है, तो यह पूरी तरह असमान व अन्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। इससे भारतीय कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और घरेलू बाजार भी प्रभावित होगा। जिला संरक्षक सुरेशचंद्र सहानी ने कहा अमेरिका में किसानों को भारी सब्सिडी व सरकारी संरक्षण मिलता है, जबकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों को अपेक्षाकृत सीमित सहायता मिलती है। ऐसे में यह समझौता छोटे व सीमांत किसानों की आजीविका, बीज उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय व पारंपरिक खेती पर सीधा असर डाल सकता है। मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा ने कहा केंद्र सरकार से प्रस्तावित समझौते को तत्काल निरस्त करने की मांग की, उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी की गई तो भाकियू आंदोलन करेंगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पनियरा राजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष फरेंदा हरिश्चंद्र पांडेय, संगठन मंत्री मुराली प्रसाद धारिया, ब्लॉक अध्यक्ष फरेंदा जगदीश सहानी सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मनरेगा—राज्यवित्त में 7.15 लाख का घोटाला उजागरः प्रधान, सचिव को नोटिस, बीडीओ की निगरानी में बन रहे पार्क में अनियमितता

संवाददाता—महराजगंज। निचलौल ब्लॉक की मेड़िया ग्राम पंचायत में मनरेगा पार्क के समतलीकरण और पंचायत भवन में मिट्टी भराई के नाम पर कुल 7,15,371 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। इस मामले में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया गया है। यह अनियमितता उस मनरेगा पार्क के निर्माण में उजागर हुई है, जिसका कार्य निचलौल की बीडीओ की सीधी निगरानी में कराया जा रहा था। गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और अब प्रधान—सचिव के साथ—साथ कई अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के आदेश पर उपायुक्त मनरेगा गौरवेंद्र सिंह और सहायक अभियंता (सिंचाई) मन्नू चौधरी द्वारा एक संयुक्त जांच कराई गई थी। इस जांच में वित्तीय अनियमितता और दोहरे भुगतान के तथ्य सामने आए।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा मद में कुल 2,71,436 रुपये की वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है। इसमें मिट्टी भराई व समतलीकरण कार्य के लिए 1,34,272 रुपये का भुगतान बिना टेंडर प्रक्रिया के सीधे ट्रैक्टर—ट्राली स्वामी के निजी खाते में किया गया। इसके अतिरिक्त, साइन बोर्ड न लगाने और कार्य से अधिक भुगतान के कारण 1,37,164 रुपये की अनियमितता भी सामने आई।

राज्यवित्त मद में भी कुल 4,43,935 रुपये का दुरुपयोग पाया गया। पंचायत भवन निर्माण हेतु मिट्टीभराई व समतलीकरण में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तीन अलग—अलग ट्रैक्टर—ट्राली स्वामियों को सीधे भुगतान किया गया, जिससे दो कार्यों में क्रमशः 2,38,054 रुपये और 2,05,881 रुपये की अनियमितता हुई।

जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कुछ अनुमानों के तहत कई स्थानों पर कार्य कराए बिना ही भुगतान कर दिया गया और संशोधित अनुमान की स्वीकृति भी नहीं ली गई।

मनरेगा पार्क का निर्माण बीडीओ की प्रत्यक्ष निगरानी में होने के बावजूद इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन अब पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया में जुटा है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो संबंधितों के विरुद्ध कठोर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

सड़क निर्माण रोकने को लेकर विवाद, प्रधान समेत ग्रामीण कोतवाली में धरने पर बैठे

संवाददाता—देवरिया। पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों द्वारा आम रास्ता के रूप में आवागमन में प्रयोग की जा रही सड़क को गुरुवार को एक व्यक्ति द्वारा ईंट लगाकर आंशिक रूप से बंद कर दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया। रास्ता अवरुद्ध होने से नाराज ग्राम प्रधान समेत दर्जन भर ग्रामीण गुरुवार को सुबह कोतवाली पहुंच गए और करीब आधे घंटे तक धरने पर बैठे रहे। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंडित हरैया के ग्राम प्रधान संदीप यादव ने दर्जनों ग्रामीणों के साथ कोतवाली परिसर पहुंचे। वे आम रास्ता अवरुद्ध किए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में जमीन पर बैठ गए। वे करीब आधा घंटा तक गांव के दर्जन भर लोगों के साथ बैठे रहे। कोतवाली पुलिस के समझाने के बाद वे हस्ताक्षरयुक्त तहरीर पुलिस को देकर बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने सड़क पर ईंट—पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया है, जिससे ग्रामवासियों को भारी परेशानी हो रही है। गांव के कुछ संभ्रांत लोगों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन रास्ता अवरुद्ध किए लोग नहीं माने। ग्राम प्रधान ने सड़क से अतिक्रमण हटवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी मामले में गांव के निवासी अनिरुद्ध तिवारी ने भी पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क से अतिक्रमण हटाने की बात कहने पर संबंधित लोगों ने उन पर ईंट—पत्थर चलाए और उनके पुत्र हरिवंश तिवारी के मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी। अनिरुद्ध तिवारी ने इसकी सूचना पीआरबी 112 को भी दी, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा।

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन अपर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता—गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा एकला, बाघागड़ा और तालनवर गांवों में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने गुरुवार कमिश्नर कार्यालय पर आक्रोश व्यक्त किया। कमिश्नर की अनुपस्थिति में किसानों ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एकला, बाघागड़ा और तालनवर गांवों के किसानों ने गीडा पर जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाया। कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। बताया कि यह जमीन उनकी आजीविका का मुख्य आधार है। इसे किसी भी स्थिति में अधिग्रहित नहीं होने दिया जाएगा। किसान खेदन लाल और प्रधान विनोद निषाद की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे।

ज्ञापन में मांग की गई कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। संबंधित गांवों की जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए।

उधर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मकसूदन त्रिपाठी ने जमीन उनकी विरासत है, उसे जबरन नहीं लिया जा सकता। वहीं, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य महेंद्र मोहन उर्फ गुड्डू तिवारी ने आरोप लगाया कि गीडा प्रशासन किसानों पर जबरन अधिग्रहण थोपने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया को पत्र लिखकर मामले को संसद में उठाने का अनुरोध किया है। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज गौतम, अभिजीत पाठक, एडवोकेट अंशुमान पाठक, सोनू पासवान, सीडी यादव, आकाश पासवान, अनिल मिश्रा, मनोज कुमार सहित क्षेत्र के अनेक किसान शामिल रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

राष्ट्रीय हड़ताल के समर्थन में निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन

संवाददाता—गोरखपुर। देशव्यापी राष्ट्रीय हड़ताल के समर्थन में 12 फरवरी को विभिन्न ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, मजदूर संगठनों और आशा वर्कर यूनियन के संयुक्त आह्वान पर नगर निगम बैंक रोड से गोलघर होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने चार श्रम संहिताएं वापस लेने, मनरेगा बहाल करने, आशा वर्करों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली बिल माफी तथा गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई रोकने जैसी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सभा के बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। सभा में राज्य स्तरीय समिति सदस्य राजेश साहनी समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर–किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। बांसगांव और उरुवा ब्लॉक में भी ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया।

बिजली कर्मी 'जेल भरो आंदोलन' के लिए बाध्य

संवाददाता—गोरखपुर। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी बिल के विरोध में गुरुवार को बिजली कर्मियों ने मोहद्दीपुर हाईडिल कालोनी में जमकर प्रदर्शन किया। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण का टेंडर हुआ तो 'जेल भरो आंदोलन', और बिल पारित करने की कोशिश पर 'लाइटनिंग एक्शन' को बाध्य होंगे। इस दौरान विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह, जीवेश नन्दन, सीबी उपाध्याय, ब्रजेश त्रिपाठी, प्रभुनाथ प्रसाद, संगमलाल मौर्य, इस्माइल खान, संदीप श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, धनंजय राजभर, प्रमोद पाण्डेय, आशुतोष राय, प्रमोद यादव, श्याम सिंह, एन के सिंह, भारतेन्दु चौबे, रणंजय सिंह, राघवेन्द्र साहू, राजेश कुमार, पीयूष श्रीवास्तव, अमरनाथ कुशवाहा, करुणेश त्रिपाठी, ओम गुप्ता, राजकुमार सागर, विजय बहादुर सिंह एवं राकेश चौरसिया के साथ विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के तमाम पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

सिद्धनाथ चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

—संवाददाता भारतीय बस्ती— बस्ती (कुदरहा)। विकासखंड कुदरहा के ग्राम पंचायत कबरा खास स्थित सिद्धनाथ चौराहे पर बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह पटेल रहे। उनके साथ मंडल अध्यक्ष मारतंड प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष जटाशंकर पाण्डेय तथा विशिष्ट अतिथि परमात्मा प्रसाद चौधरी, पारस नाथ गुप्ता एवं प्रभारीब्लॉक अध्यक्ष कुदरहा अखिलेश कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। पंचायत का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कुमार शुक्ला के निर्देशन में किया गया।

जिलाध्यक्ष जटाशंकर पाण्डेय ने कहा कि किसान आज बढ़ती लागत, खाद–बीज की किल्लत, सिंचाई की समस्या, आवारा पशुओं के आतंक और फसलों के उचित मूल्य न मिलने जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने के दावे के बजाय जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग की कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाए तथा भुगतान समयबद्ध ढंग से कराया जाए।

ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कुमार शुक्ला ने कहा कि संगठन किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। यदि प्रशासन ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने किसानों से एकजुट रहने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। पंचायत के उपरांत किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार कुदरहा परिक्षेत्र वीर बहादुर सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

इस अवसर पर फूलचंद शर्मा, मिश्रीलाल चौधरी, राम नवल गुप्ता सहित क्षेत्र के अनेक किसान मौजूद रहे। पंचायत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि उनकी समस्याओं की अनदेखी हुई तो वे संघर्ष का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे।

रामपुर में अधिवक्ता की हत्या के विरोध में वकीलों का कार्य बहिष्कार

संवाददाता—गोरखपुर। जनपद रामपुर में अधिवक्ता फारुख अहमद खां की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभागार में साधारण सभा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडेय ने की, जबकि संचालन मंत्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ने किया। बैठक में अधिवक्ताओं ने घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना की। विरोध स्वरूप गुरुवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर कार्य बहिष्कार किया। साथ ही निर्णय लिया गया कि शुक्रवार को भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू न किए जाने के विरोध में न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्व विधिक परिषद से तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इसके अलावा मृतक अधिवक्ता के परिवार को उचित क्षतिपूर्ति और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई गई। सभा के अंत में अधिवक्ता फारुख अहमद खां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

कब्र से निकलवाया गया अंश का शव

संवाददाता—अम्बेडकरनगर। मालीपुर के आशानंदपुर बरौली गांव में 9 वर्षीय छात्र अंश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बृहस्पतिवार को शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार के लोगों की ओर से स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाए जाने के बाद डीएम अनुपम शुक्ला के आदेश पर नायब तहसीलदार अमरनाथ व पुलिस की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की। अब डॉक्टरों की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।

आशानंदपुर बरौली गांव के नेत्रहीन दंपती हीरालाल और शशिकला का इकलौता पुत्र अंश जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर मालीपुर में यूकेजी का छात्र था। बीते मंगलवार को वह स्कूल गया था। परिजनों का आरोप है कि सुबह करीब 10 बजे स्कूल में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टियां होने लगीं, लेकिन विद्यालय की ओर से न तो घर पर सूचना दी गई और न ही उपचार कराया गया। ऐसे में वह घंटों दर्द से तड़पता रहा। दोपहर तीन बजे छुट्टी के बाद अंश को स्कूल बस से घर भेज दिया। घर से करीब 500 मीटर पहले चालक ने उसे उतार दिया। घर पहुंचने के बाद परिजन उसे स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। उपचार के बाद घर लेकर आ गए थे, लेकिन शाम को उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को मंजूषा नदी के तट पर दफन कर दिया था। बुधवार को मां शशिकला ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम जलालपुर को प्रार्थना पत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बृहस्पतिवार सुबह प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की टीम घाट पर पहुंची, जहां परिजनों व ग्रामीणों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए पंचनामा किया गया।

अंश तीन बहनों का इकलौता भाई था। पिता हीरालाल ट्रेन में चना बेचकर परिवार का भरण–पोषण करते हैं। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है। माता–पिता व बहनों का रो–रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और प्रशासन से जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रबंधक राजेश अग्रहरि ने बताया कि छात्र सामान्य स्थिति में बस में बैठा था। बस कुछ दूर जाने के बाद बच्चे ने पेट में दर्द की शिकायत की तो परिजनों को चालक ने सूचना दी। स्कूल प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई है। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। राजनीति के चलते अनावश्यक स्कूल को बदनाम किया जा रहा है।

जलालपुर सीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। उसी आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही साथी बच्चों व शिक्षकों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

कमिश्नर-आईजी ने तामेश्वरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया

संवाददाता—संतकबीरनगर। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव त्यागी ने जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के साथ तामेश्वरनाथ शिव मंदिर परिसर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जलाभिषेक के लिए लगने वाली कतारों की बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। मंदिर व मेला स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, अग्निशमन दल व स्वयंसेवकों की तैनाती तथा खोया–पाया केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने मेला आयोजकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत कर श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग, साफ–सफाई और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। इसके उपरांत मंडलायुक्त और डीआईजी ने डीएम व एसपी के साथ बाबा तामेश्वर धाम में प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, मंदिर के पुजारी गोसाई जी और स्थानीय ग्रामीणों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महाशिवरात्रि पर्व को सुरक्षित एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडलायुक्त और डीआईजी ने महाशिवरात्रि पर्व को आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने जनपद की शांतिपूर्ण परंपरा को बनाए रखने पर जोर देते हुए कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, साफ–सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही शिवभक्तों और मेलार्थियों के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने तथा डायवर्जन प्लान को कड़ाई से लागू कर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की। सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत—श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0—625/2017
मुतफरका नं0—318/2022
झब्बर आदि
बनाम
राम प्रसाद आदि
1/1 ज्ञानमती 1/2 गढ़ी पुत्रीगण राम प्रसाद 2. ओम प्रकाश 3. परागदीन पुत्रगण राम प्रसाद 4. जगदीश पुत्र रामकिशोर साकिन गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 28—02—2026
हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 28 माह 02 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा (आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला बस्ती
वाद सं0—609/2022
चन्द्रशेखर आदि
बनाम
उदय प्रताप
1/1 सावित्री देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी उदय प्रताप 1/2 उमेश उम्र 39. वर्ष 1/3 राजेश उम्र 29 वर्ष पुत्रगण उदय प्रताप निवासीगण छपिया तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती
तारीख पेशी 30—03—2026
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 30 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय—श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 667/1998
रामफेर
बनाम
रामनयन
1. किरन बेवा इन्दल 2. प्रभावती बेवा विक्रम 3. विजय 4. रंजित 5. राजू पुत्रगण इन्दल 6. सोहवत देवी बेवा रामफर 7. गोपाल 8. विशाल 9. पुदन 10. रूदल पुत्रगण रामफेर साकिनान मौजा लहरी तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 24—02—2026
चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्शित करने के लिये 2026 के माह 02 के 24 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा (आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मण्डल बस्ती जिला—बस्ती
निगरानी सं0—563/19
C 201917000000563
श्रीमती शान्ती
बनाम
उदयराज
1/1 श्रीमती कमला देवी विधवा उदयराज निवासी हाल मुकाम मो0 विशुनपुरवा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 4/1 अतुल 4/2 अमी पुत्रगण स्व0 अरविन्द प्रकाश यादव 4/3 सुमन देवी विधवा अरविन्द प्रकाश यादव निवासीगण मौजा कंचनपुर तप्पा बड़गोपगार परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 24—02—2026
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 24 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0— 1251 /2025
अदालत— श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला—बस्ती
हरीराम आदि
बनाम
देवर्षि आदि
1. देवर्षि 2. शिवेश पुत्रगण शोभाराम 3. सुनीता विधवा शोभाराम 4. अभिनाश पुत्र आशुतोष 5. इन्द्रनाथ 6. महेन्द्र कुमार पुत्रगण समाराम निवासीगण ग्राम मिश्रौलियाधीश तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 18—02—2026
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिश बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 18 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 11 माह 02 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला बस्ती
वाद सं0— 1010/2019
महादेव
बनाम
रामदेव आदि
प्रतिवादी—2— रामदेव उम्र लगभग 60 साल पुत्र स्व0 श्री राम प्रसाद निवासी ग्राम दौलतपुर तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 1/1 हितेष कुमार उम्र लगभग 20 साल पुत्र स्व0 राकेश कुमार पौत्र स्व0 रामदेव 1/2 श्रीमती कलावती देवी उम्र 45 साल पत्नी स्व0 राकेश कुमार 1/3 रमेश उम्र लगभग 40 साल 1/4 सुनील कुमार उम्र लगभग 35 साल 1/5 रामसुरेश उम्र लगभग 35 साल पुत्रगण स्व0 रामदेव निवासीगण ग्राम दौलतपुर तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 01—05—2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको आप 01 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0 30/2026
हरिकृष्ण उपाध्याय —सायल
1— हरिकृष्ण उपाध्याय उम्र लगभग 67 वर्ष पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद, निवासी ग्राम—भैसहिया, पोस्ट आफिस दुधौरा, तप्पा देवरावं, परगना बस्ती पूरब, तहसील—बस्ती सदर, जिला बस्ती। हाल मुकाम मकान नम्बर 1644, आवास विकास कालोनी, पोस्ट आफिस गांधीनगर, तहसील वो जिला बस्ती।
तारीख पेशी 10—03—2026
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 10—03—2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0 22/2026
हरिश्चन्द्र सिंह —सायलान
1. हरिश्चन्द्र सिंह उम्र लगभग 62 वर्ष 2. विवेक विक्रम सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष पुत्रगण स्व0 शारदा प्रसाद सिंह 3. विनीत विक्रम सिंह उम्र लगभग 49 वर्ष 4. बालेन्द्र विक्रम सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष 5. सुनील विक्रम सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्रगण स्व0 शारदा प्रसाद सिंह 6. ऊषा कुमारी उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्री स्व0 शारदा प्रसाद सिंह निवासीगण ग्राम कन्दरोपुर, पोस्ट जैतापुर, तप्पा दुबौलिया, परगना अमोढ़ा, तहसील हर्रैया, जिला बस्ती। —आवेदकगण
बनाम
सायलान
1. शर्मेन्द्र विक्रम सिंह उम्र लगभग 51 वर्ष 2. उपेन्द्र विक्रम सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्रगण स्व0 शारदा प्रसाद सिंह निवासीगण ग्राम कन्दरोपुर, पोस्ट जैतापुर, तप्पा दुबौलिया, परगना अमोढ़ा, तहसील हर्रैया, जिला बस्ती 3. रागिनी सिंह उम्र लगभग 31 वर्ष पत्नी स्व0 सत्येन्द्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम कन्दरोपुर, पोस्ट जैतापुर, तप्पा दुबौलिया, परगना अमोढ़ा, तहसील हर्रैया, जिला बस्ती। हाल मुकाम द्वारा चन्द्रशेखर सिंह पुत्र राघवराय सिंह ग्राम सिंगहाराजा, पोस्ट दुबौलिया बाजार, तप्पा दुबौलिया बाजार, परगना अमोढ़ा, तहसील हर्रैया, जिला बस्ती
— सायलान द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 19—02—2026
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 19—02—2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला बस्ती
वाद सं0— 718/2025
राम सुमेर
बनाम
अर्जुन आदि
1—अर्जुन उम्र लगभग 41 साल 2—बलिराम उम्र लगभग 43 साल पुत्रगण राम लोचन निवासीगण ग्राम—कड़जा अजमतपुर, तप्पा—कबरा, परगना—महुली पश्चिम, तहसील व जिला—बस्ती 3—रिंका उम्र लगभग 40 साल पत्नी घनश्याम 4—सुमित्रा देवी उम्र लगभग 95 साल पत्नी राम दुलारे 5—जोखू उम्र लगभग 63 साल पुत्र राम दुलारे 6—सर्वजीत उम्र लगभग 61 साल 7—हरिश्चन्द्र उम्र लगभग 57 साल पुत्रगण बिरजू 8—श्रीमती केशमती उम्र लगभग 56 साल पत्नी झिनकान 9—घनश्याम उम्र लगभग 48 साल पुत्र दयाराम निवासीगण ग्राम व तप्पा—कुदरहा, परगना—महुली पश्चिम, तहसील वो जिला—बस्ती
प्रतिवादीगण
तारीख पेशी 07—03—2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 07 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक—दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय— चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय— आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय— इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com